

encouraging voluntary agencies and supporting their activities. And last but not the least is what we can do is—I suggest, Madam, that the House should have an occasion to look into my suggestion quite seriously—to constitute a Joint Committee of both the Houses on Social Legislation, and this Joint Committee should serve as a watchdog committee on the performance and implementation of the social legislation and to report to Parliament its deliberations. These reports should be annually placed on the Tables of both the Houses and should be discussed in both the Houses.

Now, Madam, I end by saying: let us all continue to build a society in which the age-old prejudices against the girl child disappear and we have truly an egalitarian society in which there is no discrimination against the child on the ground of sex.

Thank you.

4.00 P.M.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now we will take up the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभा-पति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करना हूँ :—

कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित स्वर में प्रस्ताव मागित की जाये :—

“राष्ट्रपति ने 12 मार्च, 1990 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में अपना जो अभिभाषण दिया है, उसके लिये राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हैं।”

मन्यवर, लोकसभा के चुनाव में पूर्व देश में उच्च स्तर पर बढ़ता हुआ अछाचार विरोधित बढ़ती जागरूकता वस्तुओं की नहुँवाई, प्रशासनिक, आर्थिक, शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निरक्षर श्रमिकों का राष्ट्रीय प्रशासनिक कुशलता से जनता को जागरूक या और कांग्रेस की सरकार में निर्माण कर दिया था। लोक सभा में चुनाव में जनता ने अपनी आकांक्षी प्रशंसा की। और कांग्रेस को इधर से उधर की गलत बैठना पड़ा। 9 विधान सभा चुनावों में कांग्रेसी के चुनाव में कांग्रेस ने विधायकों के विशेषकर यह प्रचार करने का प्रयास किया कि जनता दल की सरकार का राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जनता दल की—मैं जानता हूँ कि कांग्रेसी के साथ आप का कार्य कर रही है और पक्षिक को राष्ट्रीय मोर्चे के खिलाफ पड़ाने की चेष्टा की, लेकिन इन 9 विधान सभाओं के चुनावों में जनता ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय मोर्चे की नीतियाँ और राष्ट्रीय कार्यक्रम सही हैं और कांग्रेस को फिर अपने गृह की खानी पड़ी तथा एक दो राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्यक दलों की सरकारों का गठन हुआ।

2 दिसम्बर को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रधान मंत्री ने शपथ ली। विरासत में हमें आपसे क्या मिला है आपने मतलब मेरा उपसभापति ने नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सरकार ने है।

उपसभापति : आप कहिए “इतना”

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कांग्रेस की सरकार को ही विरासत में तीन चीजें मिली हैं, जनता द्वारा उम्मीद और कांग्रेसी, दिक्कतों का बंध और राजस्व भूमि तथा वायवीय नस्त्रिय की जटिल समस्या।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) :
श्रीर खाली खजाना।

4 चीजें हमें प्राप्त हुई हैं ।

धी उभरे ब्रिजाफ जल न था...

रामस्ते पर डाल रहे हैं ।

हमारे सभी बच्चे हमारे हैं

रहा है ।

इच्छा है ।

କେଉଁଠି କିଏ ଶୁଣି ଗଲା ?

કિંમ મામલે ને ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके निवासस्थान पर उनके गार्डों के द्वारा की गई पर कंग्रेस वालों ने अंतो निम्मेदारी का अहसास नहीं किया। त्रिशूणों में तो सरकार के त्याग-पत्र हो जाते हैं, आप कहेंगे कि हो तो गया था त्याग-पत्र।

उसके बाद 31 अक्टूबर, 1, 2, 3 और 4 नवम्बर को क्या दिल्ली में हुआ और क्या देश में हुआ? काठपुर में, जदवपुर में, मरठ में और अनेकों स्थानों पर नर-संहार हुआ। अनेकों दिल्ली में तीन हजार से ज्यादा बेगुनाह आदमी मारे गये, उनका धन लूटा गया, अस्मत्ते चुरी गई, बेरफती की गई, आप लिया है कोई एक्शन आपने आ...

एक कमेटी भी बनी थी। उसको भी रोक दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया।

1984 ई. में स्वर्ण मंदिर पर ब्लू स्टार आपरेशन के कारण और 31 अक्टूबर तथा 1, 2, और 3 नवम्बर को जो सिखों का नर-संहार हुआ, उससे केवल हिंदुस्तान का ही नहीं संसार का सिख भी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के खिलाफ हो गया।

आप लोग बहुत नाराज हो रहे हैं कि जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री को हटा दिया। उन्हें हम ने नहीं हटाया, आप ने हटाया या सन् 1984 ईसवी में। इसी जगमोहन को जो आपका बहुत लाडला था, इपी के मार्फत आपने जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री को बर्खास्त कराया था सन् 1984 में। इसी गवर्नर ने जब यहाँ तुरकमान गेट पर बुलबुल चलाए थे तब भी वह संजय गांधी का बड़ा लाडला छिप्टी चेरखमैत डी. को. ए. में था। उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 ईसवी में प्रधान मंत्री बनीं तब इस गोवा का गवर्नर बनाकर भेजा था। फिर गोवा से दिल्ली को गवर्नर बनाया उसके बाद उन्हें कामनाद और योग्य हम नर जम्मू-काश्मीर में गवर्नर बनाकर 1983-84 में भेजा और वहाँ भेजकर फारुख अहमदला को सरकार को बर्खास्त

कराया। अब आप यह कहते हैं कि उनको गवर्नर क्यों बना दिया।

श्री विठ्ठलाव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : आपने भी वही किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हमने आपके आदमी को गवर्नर बनाया। यह सोचते हुए कि वह योग्य आदमी है उसको आपने गोवा से हटाकर दिल्ली में रखा और योग्य सनसकर जम्मू-काश्मीर में भेजा, हम ने भी उस की योग्यता का फायदा उठाने के लिए आपके आदमी को जम्मू-काश्मीर में राष्ट्रीय हित में भेजा।

श्रीमती सत्य बहिन (उत्तर प्रदेश) : फिर भी आपकी सरकार सीती रही... (व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सो हम कहाँ रहे थे, सो तो आप रहे थे। जनता ने बताया कि आप सो रहे थे।... (व्यवधान) यह 29 तारीख (मार्च) के चुनाव हो जाने दो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ जितनी भी आप बड़बड़ करती हैं, आपको पता चल जाएगा।... (व्यवधान)

मान्यवर, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे जम्मू-काश्मीर का मामला हो, सारे मामलों में भारत की वर्तमान सरकार सह-अस्तित्व के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर, जाति और प्रेम के आधार पर विश्वास स्थापित कर के वहाँ की जनता में आत्मीयता स्थापित कर के एक नई दिशा पैदा करना चाहती है। नए हालात पैदा करना चाहती है और नए हालात पैदा भी हुए हैं। अगर आप यह कहें कि माहव अब काले आम पंजाब में ज्यादा हुआ है, यह आँकड़े सारे पेश हो चुके हैं। मूड मंत्रीजी ने भी आँकड़े दिए थे, वह जो भरे पास मौजूद हैं। मान्यवर, पंजाब में दिसम्बर में 123 आँकड़े मारे, जनवरी में 126 आँकड़े फरवरी में 95 मारे। मगर सन् 1989 के आँकड़े पूरे मारे पास नहीं हैं। तब ही महीने के हैं। 1989 के तीन महीनों अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के 129,

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

128 और 149 हैं। उन से कम पंजाब में कत्ते आम हुआ है, जितना कि आपके जमाने में, सन् 1988 में हो रहा था।

मान्यवर, अभी आदरणीय बहिन जी बहुत जोर में कह रही थीं। वरनाला की सरकार सितम्बर, 1985 ईसवी में गठित हुई और 10 मई, 1987 ई० को आपने उनको धर्खास्त कर दिया। चलने देते हैं आप निर्वाचित सरकार को? आपने 10 मई, 1987 को बरखास्त किया था। बाद होगा आप सभी मेम्बरों को, कि 12 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति ने पंजाब के मुख्यमंत्रियों की मुक्त कण्ठ में प्रणाम की श्री और फिर 10-11 मई को उनको प्रखाम्ति कर दिया था और आपने यह कहकर बरखास्त किया था उनको, कि पंजाब की हालत बिगड़नी चली जा रही है। महोदया, वह मेरे पान आंकड़े मौजूद हैं—जनवरी में 24, फरवरी में 22, मार्च में 26, अप्रैल में 32 और जब उनको हटाया गया, आपकी सरकार आई तो उस समय 37, आगे के महीने में 42, आगे बढ़ते चले गए तो नवम्बर, 1987 में पंजाब में 88 और फिर दिसंबर में 83 हो गया। सन् 1987 के साल में तो यही हाल रहा, सन् 1988 में आपने रिकार्ड ही तोड़ दिया और फिर भी आप जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। माननीया बहिन जी, पर शर्मा नहीं जा रहा था, वह तो जनता ने आपको रोका, नहीं तो थक नहीं रहे थे। ... (व्यवधान)

महोदया, जहाँ तक रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का है। फरवरी, 1986 ईसवी में रामजन्म भूमि मंदिर का द्वार न्यायालय ने खोला था। मैं विरोधी दल नेता से यह पूछना चाहूँगा वह या उनके आदमी उत्तर देने की कृपा करें, कि जब फरवरी, 1986 ईसवी में मंदिर का दरवाजा पूजा के लिए खोला गया तो भारत सरकार के तात्कालिक गृह मंत्री ने पूरे सवा तीन साल बाद

15-16 मई, 1989 को रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग क्यों बुलाई? क्योंकि चुनाव मामले आ गए थे, इसी वजह से न? अगर आपको रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रश्न को मुलझाना था तो जिस दिन मंदिर खुला था, उसी दिन कोशिश करके आपको उस मामले को उच्च न्यायालय में भेजना चाहिए था। अब 15-16 मई, 1989 की मीटिंग करते हैं और जुलाई में उस उच्च न्यायालय में भेजते हैं। अगर आप सन् 1986 में ही इसे उच्च न्यायालय में भेज देते तो आज तक उसका मामला नथ हो जाता, उसका फैसला भी हो जाता। लेकिन आप फैसला नहीं कराना चाहते थे, आपका इरादा था पोलिटिकल कैपिटल बनाने का, आप उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे और इसीलिए आप इरादतन उसको खींचकर ले जा रहे लंबे और हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास कराया... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हमने ?... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जी हाँ, हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास करने की आज्ञा प्रदान की।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : वर्मा जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, इतना तो असह्य मन बोलिए। शिलान्यास हमने नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैंने आपको तो नहीं कहा। मेरा रिकार्ड देख लीजिएगा। मैंने कहा कि हिंदुओं की वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास कराया, शिलान्यास की इजाजत दी और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए निर्माण पर पाबंदी लगाई। जो इतनी चालाकी और चतुराई से काम करता है कि एक तरफ हिंदुओं की वोट लेना चाहता है और दूसरी तरफ मुसलमानों की वोट लेना चाहता है तो उसके लिए

दोनों की ही वोट नदारद हो गई,
मेरे मित्रों। ... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव :
आप ज्यादा बालाक निकले।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : लेकिन मेरा कहना है कि चाहे पंजाब का प्रश्न हो या जम्मू-कश्मीर का प्रश्न हो या फिर रामजन्म-भूमि और वायवरी मस्जिद का प्रश्न हो, तीनों ही राष्ट्रीय प्रश्न हैं, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं। मैं माननीय मदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों इस्सूज पर एक्जम्प्लायट करने वाली बातों को न करें, बल्कि देशहित में इन समस्याओं को मुलजाने में, हल कराने में आपस में मिश्रकर के सहयोग दें।...

मैंने कल जम्मू और कश्मीर के ऊपर पूरे भाषण सुने। खिया या जगमोहन! खिया में समस्या हल हो रही है, जगमोहन से समस्या हल हो रही है। हमने तो आपके लाडले को भेजा कि आपका लाडला है, हमने कहा कि पूरा-आध तो इन्हा भी रखो और इतना काविल कि गोवा में दिल्ली में लाए और दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में भेजा। हमने इरदनन आपके विश्वासपात को भेजा।

माननीय, इस राष्ट्र को गर्व है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को इस देश ने स्वीकार किया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य भी है कि देश की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्षता की बलि पर सबसे पहले चढ़े और सम्पूर्ण भारत के तीन करोड़ से भी अधिक हिन्दू, मुसलमान और सिख इस देश के बंटवारे के समय तबाह और बर्बाद हुए। हमारी जवान बहन और बेटियों की अस्मृतें लुटीं। इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी कुर्बानी भी हिन्दुस्तान के कट्टरपंथियों की आंखों को न खोल सकी और यह इस देश का दुर्भाग्य है कि दोनों सम्प्रदायों में कट्टरपंथिता बढ़ती चली जा रही है।

हमारी सरकार की यह चेष्टा है और रहेगी कि अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा

प्रदान की जाए। जो 15 सूची कार्यक्रम है, जो कोल्ड स्टोरेज में रखा है, रददी की टोकरी में पड़ा है, उस पर भी ईमानदारी के साथ अमल किया जाए और उर्दू जवान जो राष्ट्रीय भाषा है और मैंने भी पढ़ा है, मैं तो नहीं समझता कि अगर और भी पढ़ लें तो किसकी आपत्ति होगी। हिन्दू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं और सिख भी पढ़ते हैं। तो उर्दू भाषा को गुजरात समिति की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात को भी इस सरकार ने धोषणा की है।

मान्यवर, मैं अगर आपके माध्यम से अपने वुजुगों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से यह मालूम कर लूं कि जब आपका शासन था तो भागलपुर जैसा नरसंहार हुआ है क्या इस देश में कहीं? 6 महीने तक लगातार नरसंहार चलता रहा मेरठ में? अंग्रेज की हुकूमत रही, 3 दिन 4 दिन और 6 दिन में समाप्त हो गया, 6 महीने तक मेरठ में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा चलता रहा, सैकड़ों आदमी मलियाना अहमदाबाद, इन्दौर, कोटा, हर प्रदेश के मारे गए। कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार नहीं थी? उस जमाने की आपकी सरकार की कोई रिसॉल्यूशन नहीं थी? क्यों यह नरसंहार हुए हैं? और आप बता दीजिए कि 100 दिन से यह सरकार है, आपने बहुत दोष देने की कोशिश की है, 100 दिन के अंदर एक स्थान पर भी हिन्दू-मुसलमान में रायट नहीं हुआ! (व्यवधान)...

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर : बिहार) :
जयपुर में।

श्री पी० शिवशंकर : बिहार में होली के समय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कोई नहीं हुआ; आपस का, चुनाव का, जीत और हार का झगड़ा था।

मान्यवर, दुर्भाग्यवश देश की यूनिटरी गवर्नमेंट में राज्यों और केंद्र में कूट

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

अविश्वास का उत्पन्न होने लगा था। सरकारिया कमीशन ने संसुति भी की थी, लेकिन फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों के गठन करने पर आपकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यह सरकार निर्णय ले चुकी है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा ...

देश की तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश हित से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन भी यह सरकार करेगी। मान्यवर, पैसे की कमी है लेकिन देश की सुरक्षा की खातिर रक्षा के संसाधनों में एक पैसे की भी कमी न की जाएगी। हमारी फौजों को और हमारे जवानों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी और अगर हिन्दुस्तान का कोई शत्रु बुरी निगाह से हमारी ओर देखता है—जैसे पाकिस्तान सबक ग्रहण कर चुका है—उसको सबक सिखाया जाएगा लेकिन हम न पाकिस्तान की, न संसार की, एक इंच भूमि तो क्या, भुई की नौक के बराबर भी जमीन नहीं लेना चाहते लेकिन अगर कोई हमारी जमीन को छीनना चाहता है तो उसके लिए हमारे हिन्दुस्तान की सेवाएं हर तरीके से तैयार हैं।

मान्यवर, समान रैंक के लिए समान पेंशन, यह प्रश्न हमारे जवानों की तरफ से उठाया जाता रहा है लेकिन उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। अब इस सरकार ने उसको सिद्धांत रूप में कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है और उसी कार्यान्वित किया जाएगा।

हमारे देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है। यद्यपि तो 70 का दशक शुरू हुआ है लेकिन हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था और विश्वास रखे हुए बहुत पहले ही इसको स्वीकार किया था लेकिन लोकतन्त्र और विधानसभा के चुनावों से जो गूंडागर्दी हुई है... (व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : मेहम की चर्चा कीगिए ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : अमेठी की भी चर्चा करूंगा, मेहम की भी चर्चा करूंगा... (व्यवधान)

तो ये लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इनमें कई सीटों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है आपके बिहार राज्य के अंदर। वहां हमेशा यही होता रहा है। वहां हमेशा वृथ्वा फैलता होता रहा है। इसको चीफ टेलिक्शन कमिश्नर भी जानते हैं, फौज की सरकार भी जानती है और इस देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि बिहार में चुनाव के समय क्या होता है... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : 40 क्रिमिनल लोगों को टिकट किसने दिया है? आपके जनता दल ने दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, एक भी गलत आदमी को अगर हमारी पार्टी से टिकट दिया गया है तो वीरेन्द्र वर्मा आखिरी आदमी है किसी भी गंडे के पक्ष में, इसकी ताईद करने वाला।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हम वीरेन्द्र वर्मा पर कभी इलजाम नहीं लगाते। अगर बहुत अच्छे आदमी हैं... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं आपके खिलाफ ही तो कह रहा हूँ। आपकी पार्टी ने बिहार में बहुत से गलत आदमियों को टिकट दिए हैं, दूसरी पार्टियों ने भी बहुतों को टिकट दिए हैं। यह लोकतन्त्र के अस्तित्व के लिए, डेमोक्रेसी के अस्तित्व के लिए खतरा है और इसी कारण हमारी सरकार ने चुनाव पट्टी में शामिल पण्डित करने और व्यापक चुनाव जमाने के लिए प्रचलित राजनीति में बदलाव करने का संकल्प लिया है। हमें यह भी पता है कि लोकतन्त्र के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है।

वहाँ तक महिम में गलत हुआ, मैं स्वीकार करना हूँ। लेकिन महिम के पहले अमेठी में जो हुआ उसे भी आप स्वीकार करने होंगे। गलती तो गलती है चाहे अमेठी में हो चाहे महिम में हो। इलेक्शन कमिशन ने महिम में दोबारा चुनाव के आदेश दिए। महिम के अंदर पोलिंग स्टेशनों पर रिपोल की आजा दी थी। अमेठी में पोलिंग में हुआ था ?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा) : वर्मा जी, आपको भ्रष्टाचार कहना चाहता है कि आप तब कहाँ थे जब नुर्जमान गेट का गंगा था। तब आप कहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे थे। आज आप बातें बना रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष [डॉ० जी० विजय मोहन रेड्डी पीठासीन हुए]

श्री धीरेन्द्र वर्मा : हम तो नुर्जमान गेट वाले के हूँ मैं नहीं थे, न महिम के हक में है। आप जरा धैर्य रखो। जनता ने इतना बड़ा सबक दिया, फिर भी आप धैर्य नहीं रखते। जनता ने इतनी बड़ी टाँकर लगाई, फिर भी अकल नहीं आई ... (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : वर्मा जी आप वहाँ से यहाँ सरक गए हैं।

श्री धीरेन्द्र वर्मा : उपसभापति महोदय की आज्ञा से सरकार। ... (व्यवधान)

मान्यवर, भ्रष्टाचार इन देश में दुर्भाग्य के बहुत बड़ी हद तक पहुँच चुका था। अंग्रेजी बोलने में भ्रष्टाचार नहीं करता और को चलता था और ऊपर वाले ऊपरों से होते थे लेकिन इन कमालों में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को जाता है। आपकी सरकार के कोरुप्शन विभाग के विधायक जोषण प्रसाद विजय बनारस की। ये सब बातें समिति का दायरवा था। ये समिति ने मुझ परीक्षा छोड़ दिया कि वह नहीं गई है। मैं भी विपक्ष आने को ही था। मैं भी विपक्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ। वह सरकार समिति, विभिन्न उक्तों को भी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं दूसरी कोरुप्शन की थी कि प्रधान मंत्री की

रखे जायें तो आप नहीं माने थे। लेकिन अब प्रधान मंत्री महोदय को भी लोकपाल विधेयक में रखा जाएगा।

मान्यवर, तीन साल तक लगातार बोफोर्स केस पर शोर मचता रहा। 'बाब' पर 'बाब' दोनों नदनों में दिए गए। दोनों नदनों की सम्बन्ध प्रकर प्रकृति बनाई गई। पर नतीजा क्या निकला जून 1988 में हिन्दू में प्रकाशित हुई भ्रष्टाचार के बारे में और उसके लिए सी० बी० आई० के मुद्दे की गई जाँच के लिए लेकिन आज तक सी० बी० आई० उसके बारे में अपनी जाँच नहीं दे सकी और जब मैं नई सरकार आई है, उसने सी० बी० आई० को कहा और उसने अपनी जाँच पूरी कर ली और 14 आदमियों के खिलाफ केस भी कर दिए, सिविलरलैंड के अंदर 6 खातों को भी सील कर दिया और, मान्यवर, यह तो 64 करोड़ का मामला था, वहाँ तो एक ही खाते में 64 करोड़ है ... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नाम तो बता दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र वर्मा : सब पता चल जाएगा। अकेले बोफोर्स नहीं, पनडुच्ची इसके लिए टैलकम आया था जर्मनी में 30 करोड़ रुपए की जाँच की जा रही है। वैस्टलैंड हेलीकोप्टर जिनके बारे में मैंने तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने इसी पदन में उठाया था कि वैस्टलैंड हेलीकोप्टर के खरीद के बारे में जाँच हो, उसकी भी जाँच हो रही है। सुप्रीमको कोरुप्शन जिनके बारे में एन० जी० सी० का प्रीसेंट हुआ था ...

साढ़े छः करोड़ रुपए का मुद्दा है जिनमें सुप्रीमको, पनडुच्ची का काकी से, पनडुच्ची का मुद्दा है। ... (व्यवधान) ... 2500 करोड़ रुपए की जाँच की जा रही है। 320 करोड़ रुपए का मुद्दा है। ... (व्यवधान) ... हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोरुप्शन

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

की विधिवत और उसके स्थानान्तरण के लिए एक न्यायिक आयोग बैठाया जाएगा। उन विधिवतों को राजनैतिक स्तर पर न करके न्यायिक आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जाएगा और उनका स्थानान्तरण भी।

रेडियो और टेलीविजन की स्वायत्ता की बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था मेरे बड़े परम मित्र हैं, जिसे यह पता चले कि रेडियो का दुर्घयोग हो रहा है। कोई और कहे तो बात है लेकिन कांग्रेस के लोगों को रेडियो का दुर्घयोग और टेलीविजन का दुर्घयोग की खोज नहीं करनी चाहिए। हमने बंद कर दिया था रेडियो और टेलीविजन मुक्तता जग जमाने में जब कि आपकी हुकूमत थी।

श्री विठ्ठलराव भाधवराव जाधव : आप टेलीविजन के अटॉमोमी की बात करते हैं लेकिन जब टेलीविजन को देखते हैं तो लगता है अटॉमोमी बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हम और तुम बात कर लेंगे। नागरिकों की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने के लिए डाकघर कानून में आपने संशोधन किया था। उसका मतलब उस समय धिरोब किया था। सौभाग्य से यह सरकार उसे वापस करा जायी है। पुनः उस पर विचार होगा। उस समय आपकी मैजिस्ट्रीटो भी वहीं रहेगी। सूचना प्राप्त करने के अधिकार की भी गारंटी दी जाएगी जिस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा (कर्नाटक) : सरकार बरत गयी है। आप अपनी सरकार के बारे में बालिश। आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : अभी तो पांच साल तक आपकी मुनता होगा। धैर्य रखना होगा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आप क्या करते बने हैं, आप बताइय। हमारे बारे में क्यों कहते हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 1989-90 में देश की अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक गिरावट आयी है। जिस दिन नयी सरकार ने भार संभाला तो 13 हजार 790 करोड़ रुपए का घाटा था। वित्त मंत्री महोदय ने जब बजट रखा था तो उस समय 7 हजार 300 करोड़ रुपए के घाटे की दर्शाया गया था कि इतना घाटा होगा। करीब-करीब दुगुना यानी 13 हजार 390 करोड़ का घाटा बन गया है। आयात-निर्यात का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया था। बाहरी और अंदरूनी ऋण ने हिन्दुस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी। इन ऋणों से हिन्दुस्तान की कमर टूटी पड़ी है। भले ही दिल्ली वाले राजी हो रहे हैं। उस ऋण की अदायगी में वर्तमान प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि उनके जमाने में 15 फीसदी ऋण की अदायगी में देना होता था और अब 30 फीसदी उसकी अदायगी में देना पड़ेगा जो आभदनी होगी निर्यात के जरिए।

जहां तक भाव का मामला है, चावल और गेहूँ और चीनी, इन सब के बारे में माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सितम्बर और नवम्बर में 13 और 14 रुपए चीनी का भाव हो गया था और आज यह साढ़े सात और 8 रुपए के करीब है, और सब जगह मिलती है।

श्री जगेश बेसाई (महाराष्ट्र) : कहाँ मिलती है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप ये बातें अपने भाषण में कहिए। चावल, गेहूँ, और चीनी के भाव गिरे हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : किस दुकान पर मिलते हैं, जरा बता दीजिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : पांच साल तक आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपको दिला

दुंगा। आप मेरे से मांगिए। चावल बोनी, गेहूँ और चाय की कामलों में पहले की तुलना में गिरावट आई है। मौजूदा सरकार आत्मनिर्भरता के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने और उसको कायम करने और उसे पर चलने पर निवार कर रही है। योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है। उत्पादक रोजगार लोगों को मिले, उसमें गरीबी दूर हो, इस पर यह सरकार चयना चाहती है। क्या वांछने से गरीबी दूर नहीं होती। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने स्वयं यह कहा था कि जितना रुपा हम आई०आर० डी० पी०, डी० आर० डी० ए० और दूसरी योजनाओं में बांटे हैं उसका केवल 15 फीसदी लाभार्थी व्यक्ति तक पहुँच पाता है। यह मैंने नहीं कहा है, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा है... (व्यवधान) प्रधानमंत्री सारे देश के लिए बोलते हैं। उन्होंने यह बात कही थी... (व्यवधान) अभी आपको बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निरन्तर बढ़ते हुए आर्थिक असंतुलन को दूर किया जाएगा। महिलाओं के आर्थिक विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाज में इनको सम्मान मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। नौरो पांच-छः बहिनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम तो उनका आदर करते हैं, लेकिन वहाँ से एक महिला का आदर किया गया था। महिलाओं के सम्मान के लिए, समाज में उनको प्रतिष्ठा देने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा।

मैं अपनी बात कहने में नाकामयाब रहूँगा, अगर मैं किसानों के बावत कुछ न कहूँ। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना में साढ़े 37 फीसदी खर्च कृषि के लिए निर्धारित किया गया था। इसका विस्तार बढ़ता गया। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 21 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित किया गया। पहली योजना में तो साढ़े 37 प्रतिशत और सातवीं योजना में 21 प्रतिशत रखा है और इस सरकार ने

निर्धारित किया है 50 फीसदी कृषि पर और ग्रामीण विकास के ऊपर।

मान्यवर, टर्म्स ऑफ ट्रेड, कृषि और व्यापार की स्थिति विलकुल बिगड़ा पड़ा है और वह किसानों के खिलाफ जाती है। जिसको कहते हैं प्राइजम रिमोव्ड एंड प्राइस फेड। किसान को उसकी पैदावार का क्या मिला और किसान को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए क्या देना पड़ा। इसमें निरन्तर अंतर बढ़ता चला जा रहा है। इस सरकार की यह चेष्टा होती कि टर्म्स ऑफ ट्रेड किसानों के पक्ष में जाए, यह उनके विपरीत न रहे। इस हजार रुपए तक का ऋण खद कृषकों, सीमांत कृषकों, बुजुर्गों, दम्पकारों, मजदूरों, गरीब आदिमियों का सम्मान करने की घोषणा भी 19 तारीख के बजट में पेश की जाएगी।... (व्यवधान)... धैर्य रखें और मेरी बात सुनने की चेष्टा और कोशिश करें।

मान्यवर, हमारा देश गांवों में रहता है। गांव गांवों में पड़ा लिखा आदमी भी बेकार है और गांवों में कोई उद्योग भी नहीं है। हमारी सरकार की यह चेष्टा और कोशिश होगी कि लघु-स्तरीय तथा कृषि पर आधारित उद्योग जिनसे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, उनको गांवों में स्थापित किया जाय। 1976 में मैं इनके साथ तो नहीं था, श्री मुख्तियार सिंह मलिक के साथ, वे जनसंघ में थे लेकिन मैं उनके साथ था... (व्यवधान)... कुछ तो सुन लो जिए।

1976 में बीस-सूती कार्यक्रम बना और उस बीस-सूती कार्यक्रम में श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी का भी एक आइटम था कि हम मनेजमेंट में, प्रबंध में श्रमिकों को भी हिस्सा देंगे। 1976 से अब तक 14-15 साल से यह रद्दी का टोकरी में पड़ा रहा। इस सरकार की कोशिश है, इस सरकार का इरादा है कि श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंध में भागीदार बनाया जाय, यह सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूँ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जहाँ तक सार्वजनिक उद्योगों का सवाल है उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। इस देश में सार्वजनिक उद्योगों पर दौलत तो बहुत लगी हुई है लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार एक श्वेत पत्र इसके ऊपर प्रकाशित करेगी और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाएगी, उन सभी उद्योगों को जनता के सामने जवाब देना होगा। काम करने का अधिकार संविधान में सम्मिलित किया जा रहा है। मैं अपने माननीय मित्रों से प्रार्थना करूँगा कि इसके लिए एजेंडेशन करने की आपकी जरूरत नहीं है कि काम के अधिकार का जो आने वाला किया था उसको पूरा किया जाय। वगैरह आपके एजेंडेशन के काम का अधिकार आपके सहयोग से संविधान में संशोधन करके किया जाएगा।

(व्यावधान) . . .

मान्यवर, इस देश में 25 फीसदी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की आवादी है। यह गरीब वर्ग है। इस सरकार से सबसे पहले कदम उठाया है कि जो नव-वोड है उनको भी वही अधिकार और सुविधायें दी जाएगी, जो दूसरे हरिजनों को दी जाती है। लगातार 40 सालों से इस तरह की सुविधा आप इन गरीब आदिमियों को नहीं दे सके। इसके लिये कानून बनाकर लागू किया जायेगा।

मान्यवर 360 करोड़ रुपये भोपाल वासरी के लिए सरकार ने अनुदानस्वरूप, सहयोगस्वरूप वहाँ के लोगों को दिये हैं। (व्यवधान) . . .

मान्यवर, मेरे मित्र जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, पैदा भी नहीं हुए होंगे। सन् 1953 में काका साहब कलिनकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी। बहुत दूर सी उत रिपोर्ट की सिफारिशें मिली थी। उसका जवाब है, खूदो में दोहरी में कहीं नहीं पड़ी होगी। अभी जो पड़ी रही। उत रिपोर्ट के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। मुबारकबादी के लिए भी कुछ भी स्थापित नहीं। शायद 8 साल से ज्यादा

तो हो ही गये होंगे मंडल आयोग की रिपोर्ट को आए हुए। वह रिपोर्ट भी खूदो की टोकरी में पड़ी रही। इस सरकार का इरादा है, एक कमेटी भी बना दी है और इसमें सब में इस संबंध में हम अपनी कार्यवाही से दोनों सदनों को अवगत भी कराएंगे।

मान्यवर, विदेश नीति, संसार में भारत की विदेश नीति परी उतरी है। संसार के सभी देशों से हम ज्ञानि, प्रेम, सहअस्तित्व, गृहनिर्भरता के आधार पर अपनी कार्यवाही करने की चेष्टा करते हैं। हमारे सभी देशों से सम्बन्ध अच्छे हैं। हमने संबंध अच्छे बनाने की पाकिस्तान से भी लगातार इन चार दशकों में कोशिश की है लेकिन पाकिस्तान नफरत के आधार पर कायम हुआ था और नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना और नफरत के आधार पर पाकिस्तान कायम है। हिन्दुस्तान के खिलाफ केवल मजहब के नाम पर, नफरत का प्रचार करता रहता है। मान्यवर, अफगानिस्तान हो चाहे संसार के दूसरे मुस्लिम राष्ट्र हों, संसार का कोई भी देश हो, हमारे सभी देशों से संबंध अच्छे हैं। इस के साथ हम अपने सम्बन्धों पर गर्व कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी विदेश नीति कसौटी पर खरी और पूरी उतरी है उसी तरह से हिन्दुस्तान और रूस की मित्रता भी खरी उतरी है। हमारे व्यापारिक सम्बन्ध अमेरिका से सब से अधिक हैं। उनकी जो टेक्नीकल एडवाइस है उसका भी हम बहुत बड़ा लाभ उठा रहे हैं। हमारी किसी से भी शत्रुता नहीं है। शत्रुता हम पाकिस्तान से भी नहीं मानते हैं लेकिन पाकिस्तान हम से जरूर हृदय में शत्रुता रखता है। उसका सबका तीन दफा भारत के जवानों ने रक्षा के बहादुर दैनिक उसे मिटा भी चुके हैं। अबवर और चौका परमानवा न है, हम नहीं चाहते हैं किसी भी किसी से जवाबदार ऐसा कभी हुआ तो फिर हमारे जीवधान उसने मरना मिटाने के लिए हमारा तैयार है।

मैंने अवगत करवा है कि 70 वर्ष अत्यधिक शक्ति के कब्जे में रहने के बाद

नामोबिया 21 मार्च को स्वतंत्र हो रहा है। भारत को सरकार निरन्तर कोशिश करती रही, अकेले नामोबिया के लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी कोलोनियल देश जो भी दबे पड़े थे उनको आजादी के लिए निरन्तर कोशिश करता रहा। नामोबिया के लिए भी कोशिश करती रही। हमें बड़े भारी खुशी है कि नामोबिया स्वतंत्र हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री 21 मार्च को उनके इस जपन में उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। साऊथ अफ्रीका के यह भी खुशी का मौका है कि डा. नेल्सन मंडेला रिहा हो गये हैं। हिन्दुस्तान में आजादी हासिल करने के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है, हिन्दुस्तान के भी बहुत से नेता जेलों में हैं लेकिन नेल्सन मंडेला की कुर्बानी उन्हें दी। 27 वर्ष तक उन जालियों के जेलों में रहे भी अब रिहा हुए हैं। हमें यह आशा है कि साऊथ अफ्रीका भी स्वतंत्रता उस मापने में हासिल करेगा कि वहाँ के बहुसंख्यक लोगों की वोट का अधिकार हो और उनकी उनकी सरकार प्राप्त हो।

इस बात की वहाँ भी चेष्टा और कोशिश हो रही है। एक दो बातें और उद्देश्य में प्राप्ति बात समाप्त करता हूँ।

परिवार कल्याण पर सरकार का विशेष ध्यान है। यहाँ विज्ञान भी विकास का काम होता है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वह दिखाई नहीं देता है। मेरे पास आंकड़े भी मौजूद हैं कि सन 1951 में जब पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो हमारी वृद्धि दर क्या थी पापुलेशन की और परिवार नियोजन पर अग्रणी रुपये खर्च करने के बाद हमारी जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिफल क्या है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सन 1951 से ज्यादा हो है तब नहीं है। मान्यवर, इन परिवार नियोजन के देशों में नहीं पसार भी नहीं उठा है। देशों में सरीसृप मारिमी हैं, रोगाणु भी नहीं हैं। जगहों भी देशों को डिपेंडेंसी में नहीं हैं। डॉक्टरों भी वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। मैं अपने मंत्री प्रो. एम. से. ए. को जबरन कहूँ कि देशों में परिवार कल्याण के कार्यक्रम को सफलता-

पूर्वक चलाने में विशेष ध्यान दें। दवाइयों को भी पहुँचा कराने की कृपा करें।

मान्यवर, युवा वर्ग देश की शक्ति है अविष्य की आशा है। हमारा युवा वर्ग बड़े बड़े पदों पर नहीं आता। आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. एफ. एस., फारेल सर्विसेज में या दूसरी सर्विसेज में शहर का आदमी आता है। देर में वह पढ़ता प्रारम्भ करता है अतः इस सरकार ने उनकी कठिनाइयों का आभास करते हुए 26 साल से उनकी आयु बढ़ाकर 28 वर्ष की है। एक दफा पहले भी यह हो चुका था। माफ करेंगे, मेरे मित्र हैं जगेश्वर भाई जो, 28 वर्ष कर दो थी लेकिन इन्होंने वापस ले ली थी। इस सरकार ने 28 वर्ष कर दी है, यह कायम रहेगी, इसको कायम रखने की चेष्टा करेंगे जिससे कि गाँवों में रहने वाले लोगों को उच्च पदों की परीक्षाओं में बैठने और उन्नति तथा तरक्की करने के साधन उपलब्ध हो सकें।

मान्यवर, वर्तमान सरकार के सामने अनेकों गम्भीर चुनौतियाँ हैं किन्तु देश की जनता और आप जितने भी अटे हैं—ये तो सारे खाली पड़े हैं—आप सभी के सहयोग से उन चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करने में यह सरकार सफल होगी। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि जो भाषण राष्ट्रपति जो ने 12 तारीख को दोनों सदनों को दिया है, उसके प्रति यह हाउस कृतज्ञतापूर्वक अनुगृहीत रहेगा और उनको धन्यवाद देगा। जयहिंद।

THE VICE-CHAIR MAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) :
Shri N. E. Balaram to make his speech seconding the Motion.

5.00 P.M.

SHRI N.E. BALARAM (Kerala):
Mr. Vice-Chairman, Sir, this time we are discussing the problems of our country after holding elections in a number of Assemblies. Now I think the political picture of the country is very clear. Not only that, I think the verdict of the people is also very clear. What they want to have is a change, not only a change of party or parties, not only a

[Shri N. E. Balaram]

change of government, but what they are more interested in is a change in policies. If one looks into the speech made by the President, one can see that there are a number of indications that this Government is going to follow a number of new policies. They want a change in the policies. I am not saying that it is an easy matter. I do not think so. Because they have already inherited a number of problems which are very serious problems which will take time, which need the co-operation of all sections of the people, of all parties, to find a solution. I do not think these problems can be solved overnight.

As I said, there are a number of problems which they have inherited. A set of problems is those which have been unleashed by the forces of communalism, fundamentalism and secessionism. Of course, yesterday and today, we have been discussing them sufficiently. Though there are a number of approaches, the entire House is one on the question of how to tackle some of these problems, especially the problem of Kashmir. Tomorrow or day after, we are going to discuss the problem of Punjab. The problem of communalism will also be coming up in the coming days. I am not taking much time on any of these problems, but these are very important problems which require the co-operation of all sections of the people of the country, of all parties and groups.

Here, I would say, what I find is that this Government has got a specific approach which I could not find in the previous Government. I am not utilising this opportunity to criticise the previous Government. I am only saying what is new in their approach. There is something new, according to me. They are openly sharing—especially the Prime Minister—their views

with all the parties. They are sharing their views with us, sharing their views with the Opposition parties. They are listening to the opinions, criticisms and suggestions from all these parties and they are making a search for a national consensus on a number of important problems. This is something new in this country which did not see in the past, with the result that, I think, the political atmosphere is a little bit relaxed and the atmosphere here is less oppressive. As some historians had done in the past, they started the idea of assessing a hundred days' performance. Hundred days of Napoleon—that was the first historical assessment of hundred days. I do not know why we are getting such a method here.

Now, here also we are seeing that assessment of 100 days. Even if we assess these 100 days of activities of this Government—I am not saying that all the activities of the Government are carried out—but, if you objectively assess the activities of the Government, you can see that it has an approach of finding solutions to the problems of the country on the basis of national consensus. Not only that. They want to resurrect the old, nationally accepted policies. That also they are doing. I think my friends will also agree with me that more and more consultations, meaningful consultations—not consultation for consultation's sake but meaningful consultation—sharing of views with the Opposition parties, and loud thinking along with the Opposition parties, makes a dent to reach a national consensus on a number of issues. That is the way in which this Government is functioning. I fully support that sort of an approach. And that is why we were able to form a committee on the question of Kashmir. On a number of issues, in the future also the Government may follow the same policy and even be able to find consensus on most of the issues.

Naturally, a question will arise—why this attempt to reach a consensus policy now? The policy of consensus, according to me, is not a policy of convenience, not a policy of pragmatism nor a policy of opportunism. It is not even a tactical device to get out of some impossible impasse. I don't think so. This policy has arisen out of the objective conditions of this country and the attitude of the Government. It is out of the objective situation in the country and the subjective response on the part of the Government that this policy has arisen because there are a number of issues to be tackled. In the past it was a one-man rule. It was not a party rule in the past. I don't think that Opposition party itself will agree that it was a party rule. It was a one-man rule and that one-man rule was taking a position of confrontation. They were not following a policy of consensus or conciliation or discussion or debate, and they were not trying to understand the view points of others. They were following a policy of confrontation on many occasions. Sometimes they challenged the entire democratic opinion of this country and that is why they were forced to withdraw the Bill of Defamation. I remember those occasions. If you look at the whole past history of the previous Government, it was a period of confrontation. Fortunately, that period of confrontation is over and I pray that that period of confrontation should never come up in the country again. We should not allow the policy of confrontation to raise its head again in this country.

What we want is a policy of national consensus to solve the problems. I think this policy will bear fruit. This policy can solve a number of problems. So, this is one thing I have found in the new Government. The same thing I have seen in the President's Address also. The approach of the entire Address shows that they want a policy of consensus. Somebody

was saying that there are parties with opposition supporting the Government. I don't think my friend, Mr. Vajpayee, will deny it.

Of course, we are supporting. The parties which have got opposite views, are supporting this Government. As I said, the basis is that all of us are trying to find out solutions on the basis of consensus and the Prime Minister is keen very keen—that is a very big thing—to share his views with others. That is a new thing that I have seen, a new situation has come about. I think, this Government will continue with this policy, and that is very much represented by the speech made by the President. I said that we have inherited a number of problems. One type of problems I have already mentioned. I do not want to go into them. Again and again we have been discussing them, and we will discuss them again, the problems of communalism, Kashmir, Punjab etc. But now we are facing another set of problems. Unfortunately—I say “unfortunately”—somehow an impression has been created in the minds of people in some of our neighbouring countries. I am not saying, “All the neighbouring countries.” Some doubts have been created that India is playing a big brother role. Such doubts have been created in the minds of some of our neighbouring countries. I am not talking of all the countries, especially Pakistan, but some other countries, for instance, Nepal, Sri Lanka. Because of the activities of the previous Government an impression has been created that this country is playing the role of a big brother. Slowly this Government is trying to remove these doubts. Fortunately, this Government is trying to remove those impressions. I think this is a right thing that they are doing, they are moving in the right direction. We should not create doubts in the minds of the people of our neighbouring countries that we are behaving like a big brother.

[Shr' N. E. Balaram]

We want co-operation of all the countries, especially the South Asia countries and we should use the SAARC as an instrument for that. We should try to erase the impression which has been created during the previous regime. It should be removed. There also we want an open policy, the same approach.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Replacing Governors is the new direction.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : He is speaking on external affairs, and you are speaking on Governors.

SHRI N. E. BALARAM : I am not speaking on black money question. I know what it is and how it spoiled young men also. I don't want to discuss about that.

SHRI V. GOPALSAMY : He is talking about our relationship with our neighbouring countries.

SHRI N. E. BALARAM : I am talking about the impression created by the Rajiv Government in the minds of so many neighbouring countries that India is behaving like a big brother in spite of our saying that we are adopting a policy of non-alignment etc. etc. The result is, doubts are there in the minds of other countries. This Government is slowly removing that impression. They are not standing on prestige. They are negotiating with all the countries. They are negotiating with Nepal. They are negotiating with Sri Lanka. I hope the Government will do so even on the question of talking with Pakistan. Don't forget the people of Pakistan. Pakistan is totally controlled by a section of anti-Indian groups. There are a number of democratic sections in Pakistan. You should not forget that once it was a part of this great land. That tradition is there. Don't forget that

tradition though the division has taken place. So, on that question the Government should take a bold initiative. In spite of the difficulties, in spite of the belligerent attitude, India should take a bold initiative on the basis of the new approach that it is adopting now. These are the second set of problems facing our country, to which our Government is applying its mind.

There is another set of problems. They are very difficult problems.

When the previous Government was there, there were a number of new policies. There were about thirteen new policies—the new economic policy, the new textile policy, the new tax policy, the new education policy, the new export and import policy. My God, how many new policies were there! But what did the people say? I don't know whether the Congress Party has taken stock of the election results. So far I have not read anything about it. That is their business. But I do not ask the Congress party to have self-critical analysis of its own defeat. That is their own business. But I want them also to know that the people have already rejected almost all their policies. They want a new policy. That is the verdict. The verdict has some meaning, whether they like it or not, on all sorts of your new policies.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra) : You should talk about the verdict in Kerala.

SHRI N. E. BALARAM : The verdict in Kerala about the elections? One of your stronghold seats was lost. That is what you are talking of as verdict. The verdict is there. They did not analyse the meaning of the verdict. Instead of having an objective analysis there was a whispering going on that within three or four months this Government was going to fall. Their first question was who would be the

Prime Minister. How many people want to become the Prime Minister? They were raising such questions. Who would be the Prime Minister? The Prime Minister was elected. Now, I think they require a thorough study about their own defeat. It is a big defeat of your own policies and methods. You must accept this. This mistake should not be repeated on the part of this side. I am not going into the details of all the policies. At the time of the Budget debate I may, but for the moment I want to speak on one or two policies. What was the new economic policy? I want to know what was the net result of your new economic policy. We are facing very difficult fiscal crises, debt crises, balance of payments difficulties and a number of other difficulties. Our economy is not very healthy now. I think no economist will disagree with me on that. In spite of all the tall claims, as the President in his speech said last year that the agricultural production had slowed down, the industrial production had slowed down. Why? What happened to this new economic policy? The net result of the new economic policy was to produce more durable consumer goods for the rich and upper class and they adopted all the anti-poverty programmes for the poor people. Those were the political and economic lines which you were following.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar) : What about the foodgrains production to the tune of 175 million tonnes?

SHRI N. E. BALARAM : I agree with you on that. You study that report. What did it say? It talked about food production. I agree some production is there. I don't deny that fact, but does that alone show the sound health of the economy? Would you argue like that? I don't think. I should not deny that there is some improvement on the economic front.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : My friend, Shri Balaram, is a very learned person. In his emotional outburst he is ignoring the fact that 175 million tonnes of foodgrains production is for the benefit of the poor people.

He also must realise—if he has forgotten he should remember that—as income grows, people eat less of foodgrains. More money is spent on non-food items and to the extent that rich people are not eating that much, the magnitude of foodgrains available for the poor people is all the greater. (*Interruptions*)...

SHRI N. E. BALARAM : I think you might have read Gadgil's report about the Fourth Five Year Plan and how he criticised and how he pooh-poohed the trickle-down theory. I do not want to say more than that. Your economists have been arguing about the trickle down theory and that is what you have been repeating in the House and this has been pooh-poohed by Prof. Gadgil. Thereafter you have thought about introducing the anti-poverty programme. Do you forget that? That is what I am asking from you. I am questioning the main thrust of your economic plan. The main thrust of your economic plan was to produce more consumer durables for upper classes. That is why you have produced a big network of TV throughout the country. That is what we are facing now. I am not against the spread of TV. But what is the net result, I ask? Now, what was our TV doing? Instead of improving... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Please listen to him. He is presenting his view-point. He is presenting his side of the picture.

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV (Maharashtra) : Sir, in 1979-80, when our party came to power, the foodgrains production

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]
of the country was 120 million tons and when we left the Government, it was 175 million tons. It is an achievement of the Congress Party Government. You should remember this thing.

SHRI N.E. BALARAM : I never deny the fact that there was an increase in foodgrains production in the last few years.

I do not deny that. We have to discuss other things also in the context of the Budget. Are you contesting my main point ? My main point is, the main thrust of your Plan was the production of more durable consumer goods and you know what we are spreading through the TV now. Are we utilising the TV to spread the message of unity of our country, to raise the awareness of the common people against the dangers of the country ? What are we spreading in the TV ? We are spreading through the TV brand consciousness about these durable consumer goods. If you make a study, you will find that for the last five years, the part of the national income coming from the advertising industry has increased six times because of this. (*Interruptions*) I am saying that if the present Government also go in the same way, with the same brand consciousness propaganda, I think they will be in the soup, in difficulty. That is what I am saying. Why did the people reject you ? Why did the people give verdict against you ? It was because of your policies. The net result of your TV was that through the TV, they were spreading brand consciousness. Even a child will say, Palmolive, Palmolive. What is it ? It is called the brand consciousness. It has been condemned by all the scientists in the world. That is what your TV has been doing for so many years. Don't talk of the new economic policy. I say nothing more about it than that. Professor Thandresh P. Thakur raised a relevant point. I will reply when I get

a chance at the time of Budget discussion. Now, the second thing was education. What happened to the Educational Policy ? What is the percentage of literacy now in the country ? Where are we now ? How much we have improved ? What improvement is there ? Nothing. There is no substantial improvement. How many primary schools are there ? The condition is very poor in the country. We are ashamed to say that even today in many areas, people do not know how to write and how to read. There are a large number of villages like that. What has the education policy achieved ? We know the achievements of the New Education Policy, the New Economic Policy, the New Textile Policy, etc. I do not want to take much time. There has been a fiasco. They have not improved either the economy or the culture or anything in the country. On the contrary, they have created numerous problems for the country, for our people. That is what I am saying. There must be some self-assessment on our part.

Now, I would like to say one more thing before I conclude my speech. This Government is trying to restore the democratic traditions of our country which were slowly disappearing for the last ten years, especially for the last five years. I do not think anybody will question my statement because all of us know. (*Interruptions*).

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : I question.

SHRI N. E. BALARAM : If you question, you convince me that it is wrong. We are debating with you. (*Interruptions*). The first thing is, this Government wants debates, meaningful debates. There are two types of debates. This Government wants meaningful debates. Whatever good things you are suggesting, we will accept, we will not reject. This Government is trying to restore some of the lost democratic principles. (*Interruptions*)

For instance, there is the Lok Pal Bill. We are going to discuss it. What is the intention, what is the approach there ? There was a sort of cynicism developing inside the country, from top to bottom. There were corruption charges against the Prime Minister too. Corruption had become the order of the day. How to get rid of these things ? They are introducing the Lok Pal Bill. I think it will create some confidence among the people. If you properly debate, arrive at a consensus on the Bill and implement it in the country, you can create confidence among the people and go ahead. (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHA-PPA (Karnataka) : Please yield for a minute. We have already seen how the Lok Pal has functioned under the Janata Dal Government in Karnataka. (*Interruptions*).

SHRI N. E. BALARAM : I do not want to answer because he is my friend.

Now they are thinking of changing the Postal Bill. Do you know what it contains ? When the Bill comes you can see. Don't forget that all of you were supporting the most atrocious Defamation Bill. Your mind, mood, everything was spoiled. The entire democratic consciousness in the Congress party was spoiled at that time. Ultimately, the whole consciousness of the country rose like one man and so you were forced to withdraw it. But the mood was such in your party.

Can you imagine a party existing in the world without having inner party elections for seventeen years ? This is one of the wonders of the world. A party is existing in the world without inner party elections for seventeen years. There is no democratic sense developing. It would take some time, according to me, for it to develop in your party. This is the best opportunity for that. Now they are introducing the Postal Bill. They are introducing a Bill, the Prasar Bharati Bill. Somebody was saying that the television was used for BJP purposes or Shiv Sena Purposes. If that is so, I do not agree with that, I am totally against it. How we can do it ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : What type of democracy is there in the Communist Party ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : We are not discussing it now. We can discuss it privately.

SHRI N. E. BALARAM : I can give you a secret now. About 200 Congress workers are going to join my party the day after tomorrow in Kerala or in some other state... (*Interruptions*)... I do not want to mention the place now.

SHRI V. NARAYANASAMY : This is your imagination.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Don't reply.

SHRI N. E. BALARAM : I do not want to reply. What I am saying is that the Prasar Bharati Bill may be imperfect. It requires some amendment, I agree. But how can we control it ? How can we control, "we" meaning the people the representatives of the people ? I do

[Shri N. E. Balaram]

not want to say anything about the last Government. How it was misutilised! It was terrible. Somebody was telling that he did not want to open the television because he was forced to see one man's picture every time. Even people go to see the most beautiful picture, the picture of Sri Krishna, the picture of Balakrishna only once a day. It is the most beautiful picture in the world. It is the most beautiful picture to look at, but even that is seen by the people either early in the morning or in the evening, once in a day. Not every time. They don't like it. On the television, we were forced to see 24 hours the picture of a man, a single man. What an unfortunate situation in the country! Sir, let us have a new thinking about it. They are introducing the Bill. Do you think that the Bill is intended to misuse by this Government? You can change it. We will accept it. My point is, we want to restore, this Government wants to restore the democratic traditions in this country. By way of discussion and by reviving the democratic institutions, we are going to introduce the Bill. I would like to make only one request before I conclude my speech. The point is... (Interruptions)... I know we have differences; otherwise I would not have joined this party. Let us debate. My one request is... (Interruptions)... I was there. You know, my last speech in the AICC Session was in 1939. I am saying that I was there and afterwards I said good-bye. My one request to the Government is, they have mentioned that all the land legislations will be put in the Ninth Schedule. It is a very good thing that all the land legislations should be kept in the Ninth Schedule. Not only that, in a number of States the Agrarian Reforms Bills are not even introduced. Take for instance what is happening in Bihar. What is the root cause of violence in Bihar? What is the root cause of booth-capturing in Bihar? What is the root cause for the killing of a large

number of agricultural workers in Bihar? What is the need for organising such Senas. I would like to ask these questions. I am not asking you; I am asking myself only.

SHRI V. NARAYANASAMY :
What happened in Meham ?...
(Interruptions)...

SHRI S. S. AHLUWALIA
(Bihar) : What happened in Meham?
... (Interruptions)...

SHRI N. E. BALARAM : I
am making a point and you are not
following what I am saying. Some
people cannot understand whatever
others say. What can I do ?...
(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (Dr.
G. VIJAYA MOHAN REDDY) :
You don't listen to them. You just
speak.

SHRI N.E. BALARAM :
There is a saying in Sanskrit.

अज्ञानमादध ।

अखतरमाराधय न

उज्ज्वलं दुरविद्याभ्य विणेषज

ब्रह्मपि नखर रत्नमति ।

I will give the English rendering of it. If one is ignorant, one can be taught easily. An ignorant man can be taught easily. If a person is a scholar, he can be taught much more easily. But, in between, there is a set of people. They know something and they do not know anything else. What can you do about these people? You cannot do anything at all... (Interruptions)... Even Brahma cannot do anything and even Brahma cannot teach them. You are also that set of people. What shall I do? Nobody can teach you. That is the position now (Interruptions)...

**SHRI VITHALRAO MADH-
AVRAO JADHAV (Maharashtra):**
You think you know everything?
...(Interruptions)...

SHRI N. E. BALARAM: This
is not what I am saying. This was
written by Bartrihari and not by me
...(Interruptions)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: It
applies to you also ... (Interrup-
tions)...

SHRI N. E. BALARAM: What
I am saying is that we should imple-
ment the land legislation. They should
implement as early as possible the
land legislation throughout the coun-
try. That is what is now required. In
the past, it was neglected, terribly
neglected, with the result that the
landlords are holding the countryside
today and a large number of move-
ments are taking place. We know what
they want. This is my request.

I see the new approaches and the
changes in this and I think we will
have sufficient discussion on these
things and the President's Address
has given us an opportunity for that
and I fully second the Motion
moved by Shri Virendra Verma.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR.
G. VIJAYA MOHAN REDDY):**
Now, there are 83 amendments which
are to be moved. Now, Dr. Ratna-
kar Pandey.

DR. RATNAKAR PANDEY
(Uttar Pradesh): Sir, I beg to move:

1. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not condemn the Government's
decision to drastically scale down
the security arrangements for Shri
Rajiv Gandhi”.

2. That at the end of the Motion
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not mention about the failure

of the Central Government to
curb the activities of anti-national
and secessionist forces in Punjab
and Jammu & Kashmir.”

3. That at the end of the Motion
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not mention the steps propo-
sed to be taken by the Government
to solve the Punjab and Kashmir
problems”.

4. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not contain any concrete
steps to solve the Ramjana-
mbhoomi Babri Masjid dispute.”

5. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not condemn the failure of
the Government to curb violence
in the recent Assembly elections,
especially in Bihar and Haryana”

6. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not condemn the Haryana
Government for its alleged role in
the Meham Assembly poll in
Haryana recently.”

7. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not mention about the steps
the Government propose to take
to solve the unemployment pro-
blem in the country”.

8. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not contain any indication
of the Government's resolve to

[Dr. Ratnakar Pandey]

ameliorate the lot of women folk in the country".

9. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the steps the Government propose to take to arrest the rise in prices of essential commodities."

10. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention any steps proposed to be taken by the Government to propagate the use of Hindi for official use throughout the country".

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Mr. Kulkarni. Not here. Yes, Mr. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Sir, I beg to move:

14. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the unconstitutional and impolitic dissolution of the Jammu & Kashmir Legislative Assembly by the Governor of Jammu & Kashmir."

15. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Central Government to curb the activities of anti national secessionist forces in Punjab and Jammu & Kashmir."

16. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps proposed to be taken by the Government to solve the Punjab & Kashmir problems."

17. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps the Government propose to take against rising cost of essential commodities."

18. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps proposed to be taken to prevent abuse and exploitation of the girl child in the current International Year of the Girl Child."

29. That at the end of the Motion the following be added namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Government's action in calling for *en masse* resignations of the Governors of all the States has devalued the high constitutional office of the Governor".

30. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention that complete and comprehensive economic sanctions should be imposed against the South African regime for early dismantling of apartheid."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now Mr. Bansal.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Sir, I beg to move.

19. The at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not admit of the Governments

abject failure in tackling the explosive situation in Kashmir Valley which has deteriorated alarmingly during the last four months and poses a veritable threat to the nation's unity and integrity".

20. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not spell out the perception of the Government on the Punjab issue, its policy thereon and the action plan to deal with the same".

21. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the large-scale violence unleashed and booth capturing and rigging perpetrated with the connivance of the State machinery during the recent by-election to the Meham Constituency of Haryana Legislative Assembly."

22. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the blow inflicted on the independence of judiciary by the action of the Government in holding back the appointments of Judges which were finalised by the last Government and to give effect to which only Presidential orders were to be issued."

23. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not admit of the low priority accorded by the Government to education."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY):
Now, Mr. Kapil verma.

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move:

24. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain any specific action plan to meet effectively and speedily the grave situation prevailing in Jammu & Kashmir."

25. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address, while referring to the formation of about a dozen Committees to deal with vital problems facing the nation, singularly fails to outline any carefully formulated policy and mechanism to solve them."

26. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address taking into account the astounding changes in East Europe, Soviet Union and South Africa, does not contain any fresh approach in foreign policy."

27. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the brutal repression of the people fighting for democracy in Nepal and to the large-scale violation of human rights in that country."

28. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the shocking happenings in Meham Assembly by-election in Haryana and also to the fact that a number of candidates with criminal record have been elected to the State assemblies in the recent election."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY):
Now, Mr. Santosh Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA
(Rajasthan): Sir, I beg to move :

31. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not specify any policy for
eradication of black money.”

32. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not mention about the terror-
ist and underground activities in
the State of Assam.”

33. That at the end of the Motion,
the following be added, namely:—

“but regret that the Address
does not mention about the terrorist
and naxalite activities in the State
of Andhra Pradesh, which have
increased during the last few years”

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G.
VIJAYA MOHAN REDDY): Yes,
Mr. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया
(बिहार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

34. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में
पिछली सरकार द्वारा अपनाई जा रही
उन गतिशील नीतियों को स्वीकार नहीं
किया गया है जिनके परिणामस्वरूप
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
सफलता मिली है।”

35. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में
पंचायती राज को भारतीय संविधान के
अधीन संविधिक दर्जा दिए जाने के
लिए किसी ठोस कदम का उल्लेख नहीं
किया गया है।”

36. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में
ग्राम आदमी पर आवश्यक वस्तुओं की
बढ़ती हुई कीमतों के दबाव को स्वीकार
नहीं किया गया है और इस प्रवृत्ति को
नियंत्रित करने तथा कीमतों को कम
करने के लिए किसी कदम का उल्लेख
नहीं किया गया है।”

37. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में
चकमा आदिवासियों और बांग्ला देश में
अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचारों
और चकमाओं और हिन्दुओं के बड़ी
संख्या में इन देश में आने से भारत को
पेश आ रही समस्याओं का उल्लेख नहीं
किया गया है।”

38. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में
फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को, जिनके
काफ़ी व्यापारिक हित भारत के साथ
जुड़े हैं, पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम में
उसकी मदद करने, जिससे इस क्षेत्र में
तनाव बढ़ेगा, से रोकने के सरकार के
संकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है।”

39. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न
तो पंजाब और जम्मू और काश्मीर में
राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा आतंकवाद
और विध्वंस की बढ़ती हुई गतिविधियों की
भत्सना की गई है और न इस प्रकार
की गतिविधियों को नियंत्रित करने के
लिए किन्हीं ठोस कदमों का सुझाव
दिया गया है।”

40. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित
जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो हाल के चुनावों के दौरान बट्टर-पथियों के बढ़ते हुए प्रभाव की भत्सना की गई है और न देश में धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को मजबूत बनाने के सरकार के संकल्प का प्रतिज्ञान किया गया है।”

41. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो “मूल्यों पर आधारित राजनीति” चलाने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया है और न ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के रद्द कर दिये जाने के बावजूद मेहम विधान सभा उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया का दमन करने में हरियाणा सरकार की भूमिका की भत्सना की गई है।”

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY):
Now, Mr. Vishvjit P. Singh.

SHRI VISHVJIT P. SINGH
(Maharashtra): Sir, I beg to move:

42. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address, while mentioning the situation in Jammu & Kashmir, does not refer to the sharp deterioration in the Law and order situation in the State since the 20th January, 1990.”

43. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address, while mentioning the situation in Jammu & Kashmir, does not clarify the stand of the Government on the retention of Article 370 of the Constitution of India.”

44. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address does not mention a specific time-frame for arriving at a solution of the Ram Janam-bhoomi-Babri Masjid dispute.”

45. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address, while mentioning defence preparedness, fails to clarify the stand of the Government about the Nuclear Option.”

46. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address, while mentioning democratic institutions, fails to make any mention of the *en masse* dismissal of Governors and Ambassadors and their replacement by committed political appointees of the present Government.”

47. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address, while mentioning the placing of some Land Reform Laws in the Ninth Schedule of the Constitution, does not clearly affirm the earlier commitment of the Government to include all Land Reform Laws in the Ninth Schedule of the Constitution.”

48. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“but regret that the Address fails to mention that the interim relief to be paid to the Bhopal gas victims will be doled out in meagre monthly instalment!

spread over three years and adjusted against the final amounts awarded."

49. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the hostile stand taken by Bangladesh vis-a-vis Kashmir."

50. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to take note of the democratic aspirations of the people of Nepal."

51. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address, while mentioning the Indo-Sri Lanka Accord, fails to make a firm commitment regarding the security of the Tamil population and the devolution of powers to the North-Eastern provinces of Sri Lanka."

52. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret the Address, while mentioning our relations with the United States of America, fails to clarify our stand on the outstanding issue of our Patents Law."

53. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the signal contribution of India under the

leadership of late Smt. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi towards the independence of Namibia."

VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY):
Yes, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I beg to move:

54. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the deteriorating law and order situation prevailing in Jammu & Kashmir where the civil administration has been taken over by the militants and the Government has no control over the administration at all and there is large scale migration of minorities from that State to other States and Pakistan is openly aiding and abetting the terrorists and the Government has totally failed to restore normalcy in the State."

55. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to continuing violence and killing of innocent people by terrorists in Punjab and the failure of the Government to hold Assembly elections in that State to start the political process and to hand over the administration to the elected representatives."

56. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about violence,

booth-capturing and killing of people in recent Assembly elections in Bihar and also in Meham constituency of Haryana thereby subverting the democratic process of election and encouraging money and muscle power by the Government."

57. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the suppression of press freedom by the present Government in various States, especially in Jammu & Kashmir, after the imposition of President's Rule."

58. That at the end of the Motion, the following, be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the National Front Government's failure to control the rise in prices of essential commodities and large scale bungling in the public distribution system."

59. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the Government's failure to settle the long pending Cauvery water dispute between the Governments of Karnataka, Tamil Nadu and Pondicherry and to solve the problems faced by the farmers in these regions."

60. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the Government's failure to implement the loan waiver scheme thereby negating the announcement made

by the Prime Minister and the Finance Minister to waive loans to the farming community."

61. That at end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the steps taken by the Government for the safety and security of the Tamils living in Sri Lanka after the withdrawal of the IPKF from there."

62. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the involvement of Pakistan in the internal affairs of India by aiding and abetting the terrorists in Punjab and Jammu & Kashmir."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY):
Mr. Subramanian Swamy, Not here.
Shri Ram Naresh Yadav, Not here.
Yes, Mr. Salaria.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir):
Sir, I beg to move:

75. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the developments following the appointment of Shri Jagmohan as Governor of Jammu & Kashmir, such as the imposition of Governor's Rule, dissolution of the Legislative Assembly and the atrocities on the people and long spells of curfew."

76. That at the end of the

[Shri Shabbir Ahmad Sa'aria]
motion the following be added,
namely :—

“But regret that the Address does not indicate the time within which the democratic process in the State of Punjab will be restored and the election to the Legislative Assembly of that State will be held.”

77. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“but regret that the Address does not state that the decision of the Court in Ramjanambhoomi-Babri Masjid dispute shall be followed.”

78. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“but regret that the Address does not state the time within which the recommendations of the Gujral Committee shall be implemented without which the assurance for the promotion of Urdu is a mere eye-wash.”

79. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“But regret that the Address does not assure that the recommendations of the Sarkaria Commission shall be adhered to and that all erosion in the autonomy of the State of Jammu & Kashmir shall be undone by restoration of 1952 position.”

80. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“but regret that the Address does not contain any assurance that pending the establishment of the high level judicial commission the appointment of

High Court and Supreme Court judges shall not be made.”

81. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“but regret that there is no assurance in the Address to implement the recommendations of the Government of Jammu & Kashmir for conferring Scheduled Tribe status on Gujars, Bakarwal and Argons of that State.

82. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“but regret that the Address does not mention the steps proposed to be taken to ensure that a female foetus is not destroyed by any clinical or other means.”

83. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

“But regret that the Address does not mention the fact that 1/3rd of the territory of the State of Jammu & Kashmir and 1/3rd of its population have been separated for the last 43 years by the ceasefire line and that there are no means for the people of the State to move within the State.”

The questions were proposed.

श्री सीजा इशदिवेग (गुजरात) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए
धन्यवाद के इस प्रस्ताव पर मैं अपना समर्थन
व्यक्त नहीं कर सकता ।

मान्यवर, अभी लोक सभा का चुनाव
हुआ और नई सरकार अस्तित्व में आई ।
नई सरकार ने देश के लोगों से यह कह
कर मत मांगा था कि हम देश में परिवर्तन

लाना चाहते हैं। मान्यवर, परिवर्तन आया। परिवर्तन देश में यह आया है कि पहली बार कम मत मिलने वाले लोग मिले और उनकी सरकार प्रतिस्थापित हुई। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देश में यह परिवर्तन आया कि कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि देश की जनता ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार जो भी सरकार प्रतिस्थापित होती है उसके सामने वह विरोधी दल की भूमिका निभाये। चुनाव के बाद जो सरकार में भागीदार बने और जिन्होंने सरकार बनाई उन लोगों ने देश के लोगों को जो वचन दिए थे, जो घोषणायें की थीं, देश की जनता यह मानकर चल रही थी कि जैसे ही इस सरकार की प्रतिस्थापना होगी वैसे ही जितनी भी घोषणायें की गई थी, उनके डिगोरे में, उनकी अमल में लाया जाएगा। लेकिन मान्यवर, अफसोस है कि इस सरकार ने, सौ दिवस गुजर चुके हैं, लेकिन उसने कोई भी दिशा नहीं दिखाई है। कम से कम जो वायदे उन्होंने लोगों से किए थे, अपने चुनावी डिगोरे में जो बात कही थी उसमें से किसी एक को भी पूर्ण करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मान्यवर, प्रजातंत्र में सरकारें बदलती हैं। प्रजातंत्र में लोगों को अपना अभिगमन दिखता है और अभिगम के पश्चात् यहाँ पर किसी एक पार्टी की सरकार आती है। सरकारें आती हैं और जाती हैं। लेकिन जो भी सरकार प्रतिस्थापित होती है वह संविधान के अधीन होती है। संविधान में जो बातें बताई गई होती हैं वह उसके अधीन होती हैं। इस सरकार के सदस्यों को यह भी पता नहीं है कि वे सरकार में हैं। वे अब विरोधी दल में नहीं हैं। लेकिन क्योंकि मोर्चा बना और परिवर्तन आया। परिवर्तन, ऐसा आया कि जो एक दूसरे का मुँह दबाने को तैयार नहीं थे, जिनके नेता एक साथ नहीं बैठ सकते थे, मिल सकते थे, ऐसे लोगों ने सरकार बनाई और दोनों ने मिलकर सरकार को समर्थन दिया। मान्यवर, सरकारें आती हैं और जाती हैं। लेकिन जिसको सरकार कहते हैं वह सरकार सम्पूर्ण समय के लिए देश में होता है। चाहे यह सरकार हो

और चाहे यह सरकार हो। लेकिन उस सरकार के देश के साथ जो वायदे किए होते हैं, विदेशियों के साथ जो वायदे किए होते हैं उन वायदों को निभाना नई सरकार का परम कर्तव्य होता है। इस सरकार को यह भी पता नहीं है कि दूसरे देशों के साथ जो करार किए गए हैं और दूसरे देशों से जो हम सहायता लेने जा रहे हैं, उनके एक अंश के कारण उसका क्या परिणाम हो सकता है। इनको यह पता नहीं है। मान्यवर, इन्होंने आते ही यह कहना शुरू कर दिया कि देश का खजाना खाली है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली कांग्रेस सरकार के शासन में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब कि हमने विदेशों से लिए ऋण की अदायगी में एक भी दिन का विलम्ब किया हो और हम डिफाल्टर रहे हों। जो आज सरकार में बने हैं उनको यह पता नहीं है कि कितनी ही सहायता बाहर के देशों से भी लेनी पड़ती है। आज विदेश में लोग कह रहे हैं कि जब सरकार का प्रधान मंत्री यह कह रहा है कि देश का खजाना खाली है तो फिर हमारा भुगतान कैसे होगा। इससे और सहायता देने के बारे में उन लोगों के मानस में एक संशय पैदा हो गया है। आप कम से कम यह समझ लें कि आप सरकार में बैठे हैं। आपको सरकार चलानी है। मान्यवर, आप आंकड़े देकर बताएँ कि कहां खजाना खाली है। आप हमको बतलाइये। मान्यवर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब विरोधी दल की ओर से सबसे पहला भाषण यहाँ पर हो रहा है तो मुझे खेद है कि मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। मान्यवर, वक्त्रों की कीमत होती है।

मान्यवर, मैं आपका याद दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम हिन्दुस्तान की जो उज्जत अन्तर्राष्ट्रीय बजार है, इसको बनाए रखिए। दूसरे राष्ट्रों के साथ जो करार किए गए हैं वह करार सरकार के सरकार के साथ होते हैं और एक देश की जनता और दूसरे देश की जनता के साथ करार होता है। पिछली सरकार ने जो करार किए हैं आप उनको

[श्री बीजाई शर्मा]

रिश्ते बनाना चाहते हैं इससे अन्तराष्ट्रीय बाजार में आपकी क्या कीमत रह जाएगी? मान्यवर, भूटान के साथ हमने हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में करार किया है, उसको आप रिश्ते बनाना चाहते हैं। इससे कितनी बिजली हम उत्पन्न करना चाहते थे? आपकी इज्जत अन्तराष्ट्रीय बाजार में क्या होगी? अगर आप दूसरे देशों के साथ करार करने जायेंगे आने वाले समय में आपकी क्या कीमत रह जायेगी कम से कम आप समझदारों के साथ, जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व कीजिए। थोड़ा सी समझदारी से चलिए। हमें तो अनुमान है और अनुभव के आधार पर हम बतायेंगे कि इस देश का विरोधी दल कैसा हो सकता है। जहाँ समर्थन की बात है उसे हमने राज्य सभा में मैजोरिटी में रहने हुए भी समर्थन दिया है। हमने कहा है कि हम रचनात्मक सहयोग देंगे। मैंने सदन में आग्रह किया था उन लोगों को हम से धराने की जरूरत नहीं है लेकिन जिनका समर्थन ले कर बैठ हो इन लोगों को जरा गहराई में जा कर सोच लीजिए, समझ लीजिए। हम तो चाहते कि आपकी सरकार चले, पूरे पांच साल तक आप चलाइये। पांच वर्ष के लिए पहले भी आपकी सरकार आई थी। हमने तो उसकी नहीं तोड़ा था। वह सरकार अपने ही बोझ से टूटी थी। इसलिए ऐसे कार्यक्रम इस देश में चलाइये जो जनहित के कार्यक्रम हों। जरा भी जनहित का कहीं भी अवरोध किया गया तो कांग्रेस पार्टी इस राज्य सभा में और लोक सभा में डर कर उसका मुकाबला करेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो नीति अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में हम लेकर चले हैं हमारे देश की इज्जत उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ राष्ट्र को जो नान-अलाइनमेंट की नीति हम ले कर चले थे उस नान-अलाइनमेंट की नीति के कारण पूरे विश्व में हम तीसरे सत्ता के रूप में स्थापित हुए। इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए पंडित जवाहर लाल नेहरू को और उनके बाद आने वालों को इंदिरा जी को और राजीव गांधी, जो को उन्होंने इस बात की समझ से आगे

बढ़ाया और पूरे विश्व में जनमत तैयार किया जो भारत के समर्थन में था। आज कितने दिन हुए हैं? 100 दिन और 100 दिन में अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय बाजार में आपने हिन्दुस्तान को कहाँ ला कर के खड़ा कर दिया है। आज के अवसर पर विदेश मंत्री गुजराल जी का एक निवेदन छया है। मेहरवानी कर के आप जिम्मेदारी में सरकार को चलाइये। इस किस्म का विदेश मंत्री का निवेदन छया है नान-अलाइनमेंट के बारे में कुछ राष्ट्रों के बारे में तो क्या कीमत रह जाएगी भारी अन्तराष्ट्रीय बाजार में? इसलिए मेहरवानी कर के जिम्मेदारी से सोच सोच कर चलिए कि आप सरकार में बैठें हैं। इतने ही दिनों में, 100 दिनों में यह बात हो गई। बड़े झुम झुम कर कह रहे थे कि इस सदन में कह रहे थे बाहर जा रहे थे कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कांग्रेस सरकार बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनानी रही है। अब 100 दिनों में कितने मैत्रीपूर्ण सम्बंध आपने बना दिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक विदेशी राष्ट्र का एम्बेसडर आ कर, उसका विदेश मंत्री आ कर इस देश की धरती पर आ कर इस देश के लोगों को गालों दे सकता है, इस देश के लोगों को धमकी दे सकता है, ईरान के साथ विपत्ती करने के लिए हम किम को भेज रहे हैं? कम से कम आपको अन्तराष्ट्रीय लेवल की तुलना समझ कर आगे बढ़िए। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ इतने वर्षों में हमने अपनी कीमत को अंतराष्ट्रीय बाजार में खड़ा किया, एक दर्जा बना कर हम खड़े हुए हैं। कश्मीर का मामला आया। इस पर बड़ा बहस हो चुकी है। लेकिन कश्मीर के मामले में अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में मैं पूछना चाहता हूँ। पिछले 43 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था जो स्टैंड पिछले सालों में कुछ विदेशी सरकारों ने लिया है, इसके पूर्व लिया था। हम से समर्थन करवाते हैं, हमसे लोगों से समर्थन करवाने हैं। क्यों? कम से कम यह जिम्मेदारी आपने ली है तो इसका अहसास कराइये, अपने कार्यों से और अपनी नीतियों से। बड़ी मेहनत से इस देश की विदेश नीति हमने तैयार की है और विदेशों में अपना नाम ऊंचा किया है।

इसलिए मेहरबानी करके, मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी नीतियाँ चलाईये जिनमें नान-एल।इमेंट मूवमेंट और ज्यादा अधिक सक्षम हों, मजबूत हो और कारगर बने और इस देश की हित रक्षा में आगे बढ़े ।

मान्यवर, वादे तो बड़े बड़े किये थे । आज वित्त मंत्री जी ने कह दिया । हम तो मान रहे थे जिस बात की चुनाव में आपने घोषणा की थी और जिस पर आपने लोगों का मत लिया था, जो आपने यह कहा कि हम किसानों के ऋणों को माफ करेंगे, इसमें बड़े किसान भी उन्होंने कहे थे, छोटे किसान भी कहे थे, सीमांत किसान भी कहे थे और आर्टीसन्स भी कहे थे लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं इसका इन्टीमेंशन मुझे नहीं मिला । अब घुमा फिराकर, अपने वादे से हटकर आप स्माल फार्मर्स और मॉर्जिनल फार्मर्स तक लिमिटेड होना चाहते हैं ।... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) : मैरा पाइंट आफ आर्डर है । महोदय, देखिए इतनी इम्पाटेन्ट बहस चल रही है और यहां कोई भी सीनियर मिनिस्टर हाउस में हाजिर नहीं है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में इन लोगों की कितनी रुचि है यह इससे दिखता है ।... (व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए... (व्यवधान) इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : (बिहार) : यह राष्ट्रपति का अभिभाषण है... राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उपस्थित रहना चाहिए... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to know what the definition of seniority is. There is nothing like that. There is no such definition of seniority. I am listening.

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab) : By now he should have sent word to the Home Minister or somebody else.

(Interruptions)

DR. RAJA RAMANNA : Nothing doing.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The way the Parliament is being treated by the Ruling Party is bad. You also look at the number of their Members. Not more than 5 Members are there on the Treasury Benches. I do not want to raise a point regarding quorum.

(Interruptions)

SHRI MIRZA IRSHADBAIG : This is the first speech on the Motion of Thanks on the President's Address.

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV : I would request the hon. Minister, through you, not to make a mockery of this House. Some senior Minister must be present here. He has to reply to this debate.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी अभी राज्य मंत्री जी ने कृच्छ्र अल्फाजों का प्रयोग किया है...

उपसभाध्यक्ष (डा जी विजय मोहन रेड्डी) : ठीक बोला है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : ठीक नहीं बोला है... (व्यवधान) उन्होंने बोला है यह सब चलेगा Is it a dictatorship उन्होंने कहा है सब चलेगा... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN : (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) it is not a dictatorship.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M.S. GURUPADASWAMY) : I appreciate your feelings. I always

maintain that no Minister and no Government should insult the House in any manner or individual Members. I had some urgent work. I went there. I have come back. If there is any feeling in your mind that a senior Minister is not present. I would like you to appreciate my problem. I had to go there urgently and I came back. I do not mean any insult to the House at all.

SHRI S. S. AHLUWALIA : It was done by your junior Minister. It is a very serious thing. He said : "Nothing doing".

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : He should know what he has to say in Parliament as a Minister.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Sir, when there is a discussion on the President's Address and when the first speaker on this side speaks the convention is that... *(Interruptions)*... the Prime Minister is present. But, unfortunately, this time, even the Cabinet Minister is not present. Always, it is a convention in this House that when the first speaker from this side speaks on the President's Address, even the Prime Minister is present. That is the convention of the House.

SHRI M.S. GURUPADA-SWAMY : If there is convention, I mean to maintain the convention. I repeat what I said earlier. There is no motive in this at all. I have come back. I have taken note of your feelings.

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, with all humility, I have to say that the words used by the hon. Minister of State were 'nothing doing; the House will go.' He should know that he is talking to the Members of Parliament in the Parliament, not to his junior officers.

(Interruptions)

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : It is not un-parliamentary.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : You are all speaking without the permission of the Chair.

(Interruptions)

SHRI M. S. GURUPADA-SWAMY : May I again say, please do not make an issue of these things ? After all, as Members of Parliament, we have to be generous to each other. *(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, you please ask for the record and see what the hon. Minister of State said.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : that is all right...

SHRI S. S. AHLUWALIA : He should learn how to behave with the Members of Parliament. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mirzasahib, please carry on.

श्री मोर्जा इश. बेग : मानवर, इस सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में श्री एक वान कही। (व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, those words should be deleted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : No, no.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What are you saying, Sir ? They are not to be deleted ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : What ?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : If something was said which is not really to be said to the Members...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : I have been listening to him. There is nothing that has been said...*(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, you go through the record.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mirzasahib, please carry on.

श्री मोर्जी इशदिबेग : सान्यवर,
... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Already the Leader of the House has explained the matter satisfactorily. There is nothing unparliamentary. He was volunteering to give you the reply that he is attending to the work...
(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The question is as to what the Minister of State has said here.

SHRI S. S. AHLUWALIA
Can he repeat his words ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mirzasahib, carry on.
(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I seek your protection. I have said something. Kindly do not overlook it and ask for the record.

SHRI S.S AHLUWALIA : We want your ruling on this.
(Interruptions)

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have the greatest respect for the hon. Minister of State. I know about his career, I know his background. I have great respect for him. But he is not familiar with the conventions of this House. As Mr. Gurupadaswamy, the hon. Leader of the House has just now said, the convention in this House is that when the first speakers are speaking, there is a senior Minister present.
(Interruptions) One minute, please. That protest was lodged quite vehemently by our side. And in response, the hon. Minister of State with great annoyance said, "nothing doing."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : No annoyance in that. Let us not infer something which is not intended.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : He was annoyed and he said "nothing doing", and sat down.
(Interruptions) All I have to say, Mr. Vice-Chairman, Sir, and my request to the hon. Minister of State through you is to say that he withdraws his remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : No, no. We will go through the record.

6.00 P.M.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : Why cannot he withdraw his remarks ? That will solve the problem.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : That is all right. You please carry on, Mirzasahib.
(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, we seek your protection. Please do not defend the Minister like that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : It is not a question of defending the Minister....

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We seek your protection. Please do not defend the Minister like that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : No, no. (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We have all the respect and high esteem for the hon. Minister of State. But he must realize that we are functioning in the Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : That is all right, we will go through the records.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What will you do after going through the records ? Please tell us. Just assure the House what you will do.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : You have asked that the record must be gone through and I have assured you that I will do it.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : He has said nothing unparliamentary. There is no point in going through the records because he has said nothing unparliamentary.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : There the matter ends.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I am sorry, there the matter does not end. (Interruptions);

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : You go through the records and then decide. If these words are there, you delete them.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I appeal to the Leader of the House.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : You must go through the records.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mr. Mizra, please proceed with your speech. (Interruptions). I cannot say nothing more than this that I will go through the records.

DR. RAJA RAMMANA : Mr. Vice-Chairman, Sir, I did not really know that this is going to cause so much feeling of hurt to the hon. Member. Therefore, I withdraw what I said and I am sorry that it was done.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : Well spoken. Very good.

SHRI V. GOPALSAMY : Your colleague, yesterday, do you know how he behaved ? And you were keeping quiet.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : I have an announcement to make.

ANNOUNCEMENT RE: RECOMMENDATION OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 15th March, 1990 recommended that the house should sit upto 8.00 p.m. today and from tomorrow, the 16th March, 1990, should sit upto